Result Mitra Daily Magazine

बांग्लादेश में आंदोलन

हालिया सन्दर्भ :-

- बांग्लादेश में घोषणा की गई है कि 17 जुलाई 2024 से सभी निजी एवं सार्वजनिक विश्वविद्यालय अनिश्चित काल तक के लिए बंद रहेंगे।
- देश भर में सरकार के खिलाफ हो रहे हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए यह फैसला किया गया है।

मामला:-

- दरअसल बांग्लादेश उच्च न्यायालय ने 5 जून को एक पूर्व के फैसले को पुनः बहाल किया गया, जिसमें सभी प्रकार के सरकारी नौकरियों में स्वतंत्रता सेनानियों एवं उनके वंशजों के लिए 30 % सीटें आरक्षित करने का प्रावधान है।
- बांग्लादेश सरकार द्वारा यह नीति पहले भी लाई गई थी, लेकिन छात्रों द्वारा किए गए भारी आंदोलन के बाद बांग्लादेश उच्च न्यायालय द्वारा 2018 में आरक्षण के इस प्रावधान को निरस्त कर दिया गया था।
- अब तक हुए हिंसा में 600 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं, जबकि 6 लोगों की मौत हो चुकी है।
- नवनियुक्त प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आंदोलन को शांत करने के लिए कोई विशेष कदम नहीं उठाया है, बल्कि उनके एक बयान ने, जिसमें उन्होंने आंदोलनकर्ता को रजाकार कहा है, आग में घी डालने का काम किया है।

आरक्षण प्रणाली

- बांग्लादेश में लगभग 4 लाख स्नातकों द्वारा 3000 प्रतिष्ठित सरकारी नौकरी के लिए प्रतिस्पर्द्धा होती है।
- 2018 तक बांग्लादेश में सरकारी नौकरियों में 50 % सीटें आरक्षित थी।
- जिसमें 30% , 1971 में बांग्लादेश की आजादी के लिए लडने वाले परिवार के सदस्यों के लिए, 10% महिलाओं के लिए, 10 % अविवाहित जिलों के लिए, 5% आदिवासी समुदायों के लिए तथा 1% विकलांगों के लिए आरक्षित है।
- इस प्रकार खुले प्रवेश के लिए उपलब्ध सीटों की संख्या 44% है।

विवादास्पद आरक्षण :-

- स्वतंत्रता सेनानियों को दिया जाने वाला कोटा कई मामलों में विवादित है।
- लोगों का मानना है कि वर्तमान सरकार आवामी लीग (शेख हसीना की पार्टी) के प्रति समर्थन जताने वाले लोगों के पक्ष में है।

- आवामी पार्टी ने बांग्लादेश मुक्ति संघर्ष का नेतृत्व किया था।
- कोटा प्राप्त उम्मीदवारों के लिए विशेष परीक्षाएँ आयोजित करना एवं प्रत्येक श्रेणी के अलग-अलग उम्र सीमा का निर्धारण विवाद के कारणों में था।
- सबसे ज्यादा निराशा वाली बात लोगों के लिये यह है कि कोटा में कई सीटें उम्मीदवार न मिल पाने के कारण खाली रह जाती है, लेकिन अन्य लोगों का नाम मेरिट सूची में होने के बावजूद वे बेरोजगार रह जाते है।
- अप्रैल 2018 में शिक्षकों एवं छात्रों द्वारा उपरोक्त आरक्षण को 10% तक सीमित रखने के उपक्रम में आंदोलन किया गया था।

- भीषण आंतरिक प्रदर्शन और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विरोध के बाद शेख हसीना सरकार ने सभी कोटा यानि 30% हटाने की घोषणा की।
- वर्तमान आंदोलन में आंदोलनकर्ता सभी सरकारी नौकरी से भेदभाव पूर्ण कोटा हटाने, संविधान में निर्धारित पिछडी आबादी के लिए कुल आरक्षण को 5% तक सीमित करने और इस बदलाव को सुनिश्चित करने के लिए इस संबंध में संसद में एक विधेयक पारित करने की मांग कर रहे हैं।

हसीना का "रजाकार" हास्य-व्यंग :

- शेख हसीना ने प्रेस कांफ्रेंस में कोटा प्रणाली का समर्थन करते हुए कहा था कि क्या केवल रजाकार के ही बच्चे प्रतिभाशाली हैं, स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चे एवं पोते प्रतिभाशाली नहीं हैं?
- पिछले कई वर्षों से शेख हसीना की आवामी लीग अक्सर अपनी सरकार के आलोचकों को "रजाकार" से संबोधित करती रही है।
- रजाकार, जिसका शाब्दिक अर्थ स्वयंसेवक होता है, 1971 में पाकिस्तानी जनरल हिक्का खान द्वारा स्थापित एक अर्द्धसैनिक बल था।
- रजाकारों का प्रमुख कार्य बांग्लादेशी मुक्ति आंदोलन को रोकना एवं पूर्वी पाकिस्तान (वर्तमान बांग्लादेश) पर इस्लामाबाद के नियंत्रण को मजबूती से स्थापित करना था।
- बांग्लादेश इतिहास में क्रूरता के मामले में इन्हें पाकिस्तानी सैनिकों से भी बुरा माना जाता है, जो मुक्ति संघर्ष के दौरान बंगाली नागरिकों का बलात्कार एवं नरसंहार करने में आगे थे।

Result Mitra